Newspaper Clips

December 29, 2016

Millennium Post ND 29.12.2016 P-03

Run incineration plants in Delhi at optimum capacity: NGT

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: In order to deal with huge quantities of trash, the National Green Tribunal has warned of imposing environmental compensation of Rs 5 lakh per violation on Delhi civic authorities whenever the waste-to-energy plants at Narela and Ghazipur are not run at their optimum capacity.

A Bench headed by NGT Chairperson Justice Swatanter Kumar also noted that there was no clear roadmap ready to deal with the massive quantity of waste generated in the city which remains with the municipal corporations after part of it is sent to these plants.

"We expect both these plants to operate to their optimum capacity without causing any pollution either in their processing or through their emissions. They shall operate strictly as per the prescribed norms in relation to ambient air quality, stack emissions provided under the Air Act and collect and dispose of waste strictly in terms of Solid Waste Management Rules, 2016.

"In the event, they are found at default at any one point of time, they shall be liable to pay environmental compensation of Rs 5 lakh for each default," the Bench said.

The tribunal said the default would be determined by the joint inspection team comprising member secretaries of Central Pollution Control Board, Delhi Pollution Control Committee, senior scientist from Environment Ministry and a member to be nominated by the Director of IIT, Delhi.

The Bench also reserved its order on a petition filed by residents of Sukhdev Vihar, alleging that the plant in their area was releasing "toxic" emissions, affecting their health. The residents had submitted that the plant had obtained an environmental clearance, authorisation and consent to operate (CTO) on the condition that it would use RDF and biogas technology to convert waste to energy.

But contrary to its promise, it has allegedly been incinerating mixed waste, which has lowered its efficiency and causing air pollution, it said.

Times Of India ND 29.12.2016 P-11

Sharp fall in offers at IITs this year

Somdatta Basu & Udit Prasanna Mukherji | TNN

Kolkata: Job offers have dwindled sharply at some of the country's top technology campuses in the first phase of recruitment. IITs at Kharagpur, Kanpur and Roorkee have registered a significant slump in recruitments. At IIT Mumbai, Madras and Guwahati, the total number of offers has gone up, but offers per firm have reduced. Large recruiters like Coal India, Microsoft and Goldman Sachs have been conservative in handing out letters.

IIT Kharagpur got 1,080 offers against 1,300 last year while IIT Kanpur has seen the number fall to 725 from 800. India Inc, has not directly linked this to note ban, but most of them have adopted a wait-and-watch policy owing to lower growth forecast for this fiscal. "Companies which reduced offers informed that it is due to the global slowdown," said a member of the All-IIT Placement Committee. Microsoft made only nine offers at IIT Kharagpur (25 last year), six at IIT Kanpur (21 last year) and 17 at IIT Roorkee (30 last year).

Debashis Deb, placement cell chairman at IIT-Kgp, said the slump could be due to the absence of startups this year.

Virat Vaibhav ND 29.12.2016 P-06

विश्लेषण : गंगा सफाई अभियान की धीमी गति पर चिंता जता रहे हैं बिभाष

कब तक साफ हो पाएगी गंगा?

भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा एक बार फिर चर्चा में है। सिर्फ राजनीतिक कारणों से ही नहीं, एक तरफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सात आईआईटी के कन्सोर्शियम को तलब किया है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड हाइकोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए केंद्र और उत्तराखंड सरकार को कड़ा निर्देश जारी किया है। कन्सोर्शियम ने ट्रिब्यूनल को बताया कि केंद्र और राज्य के क्रियान्वयन के बीच तालमेल न होने के कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है। गंगा की जब भी बात होती है, तो उसे वाराणसी और हरिद्वार को संबंध में ही देखा जाता है, विशेषकर वाराणसी, कुछ आस्था के कारण और कुछ राजनीतिक कारणों से। वाराणसी शहर भी हाल में अपने प्रदूषण स्तर के कारण चर्चा में रहा है। गंगा गोमुख से निकल कर देश के पांच राज्यों में ढाई हजार किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करते हुए देश के आधे से कुछ कम जनसंख्या के लिए जीवन का प्रवाह और आस्था की धारा है। लेकिन, अपनी यात्रा में गंगा एक बड़ी जनसंख्या के जीवन को पखारते हुए लगातार गंदी होती गई है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक इकाइयों से कदम मिलाते हुए घरेलू मैले और रासायनिक कचड़े को ठिकाने लगाने के वैज्ञानिक उपाय नहीं किए गए। कानून और नियम तो बनाए गए, लेकिन उनको लागू करने में कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई। नतीजा यह हुआ कि गंगा एक्शन प्लान के दो दौर के बाद और अब गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि गंगा और गंदी हो गई। गंगा सफाई के अब तक सारे प्रयास असफल हुए हैं और हमारी कमजोरियों की कलई खोलते गए हैं।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1979 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जो अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहलाता है, को जल प्रदूषण पर एक समग्र रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। यह रिपोर्ट वर्ष 1985 में केंद्र सरकार को सौंपी गई। फरवरी 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 14, जून 1986 को वाराणसी में गंगा एक्शन प्लान का प्रथम दौर प्रारंभ करते समय गंगा को फिर से स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया था।

> *तमाम रिपोर्टों के मुताबिक, गंगा में प्रदूषण का मुख्य कारक, लगभग पचहत्तर से अस्सी प्रतिशत, शहरों से उड़ेला जा रहा घरेलू मैला है। बाकी हिस्सा औद्योगिक प्रतिष्ठानों से प्रवाहित किए जा रहे जहरीले उत्सर्जन हैं। गंगा एक्शन प्लान घरेलू मैले का उपचार तथा औद्योगिक उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए एक फौरी कार्यक्रम था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के समक्ष आईआईटी कन्सोर्शियम का बयान- क्रियान्वयन एजेंसियों की बहुलता और उनके मध्य सामंजस्य की कमी गंगा सफाई की प्रगति में बाधक सिद्ध हो रही है- सही सिद्ध हो रहा है।*

तमाम रिपोर्टों के मुताबिक, गंगा में प्रदूषण का मुख्य कारक, लगभग पचहत्तर से अस्सी प्रतिशत, शहरों से उड़ेला जा रहा घरेलू मैला है। बाकी हिस्सा औद्योगिक प्रतिष्ठानों से प्रवाहित किए जा रहे जहरीले उत्सर्जन हैं। गंगा एक्शन प्लान घरेलू मैले का उपचार तथा औद्योगिक उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए एक फौरी कार्यक्रम था। प्रथम दौर में गंगा के किनारे स्थित पच्चीस बड़े शहरों को लक्ष्य किया गया। इस दौर में 433.3 करोड़ की राशि खर्च हुई। गंगा एक्शन प्लान का प्रथम दौर मार्च 2000 में बंद कर दिया गया। इसी बीच वर्ष 1993 में गंगा एक्शन प्लान का दूसरा दौर 1498.86 करोड़ रुपए के प्लान के साथ यमुना, दामोदर, गोमती और महानंदा नदियों की सफाई के लिए शुरू कर दिया गया। बाद में गंगा एक्शन प्लान को नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान में मिला दिया गया। इसी बीच सन् 2009 में नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्राधिकरण की संस्थापना कर दी गई। और अब नेशनल गंगा रिवर प्राधिकरण के क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की स्थापना कर दी गई है। इसके अतिरिक्त एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की स्थापना कर बीस हजार करोड़ रुपए के आउटले के साथ पंचवर्षीय नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी प्रारंभ कर दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के समक्ष आईआईटी कन्सोर्शियम का बयान- क्रियान्वयन एजेंसियों की बहुलता और उनके मध्य सामंजस्य की कमी गंगा सफाई की प्रगति में बाधक सिद्ध हो रही है- सही सिद्ध हो रहा है। एक प्रश्न के जवाब में कन्सोर्शियम ने यह भी बताया कि उन्हें जो आंकड़े राज्य सरकारों और विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त हो रहे हैं, उनकी जांच वे नहीं करते हैं।

इस प्रकार देखा जा सकता है कि धनराशियां आवंटित कर खर्च की जा रही हैं, लेकिन प्रगति का सही आकलन नहीं हो पा रहा है। गंगा सफाई अभियान में खर्च हुई राशि के सदुपयोग पर बार-बार प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। साल 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित योजना आयोग की एक समिति ने स्वीकार किया कि यद्यपि कि गंगा सफाई अभियान की प्रगति सकारात्मक रही है, लेकिन उपलब्धियां आशा के अनुरूप नहीं रही हैं।

उद्योग के साथ कृषि पर भी उचित नियंत्रण की आवश्यकता है। पूरे गंगा नदी बेसिन में फसल-चक्र पानी की उपलब्धता के अनुसार तय होना चाहिए। खेती में रसायनों के उपयोग पर नियंत्रण होना चाहिए। गंगा में घटता जल-बहाव भी बड़ी चिंता का कारण है। इसके लिए दोष गंगा पर बने बांधों पर मढ़ दिया जाता है, लेकिन गंगा में जलधारा की गति बनाए रखने में तालाबों के लिए कोई भूमिका नहीं तय की गई है।

नेशनल गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना गंगा एक्शन प्लान से प्राप्त सीख पर आधारित समन्वित कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए किया गया। इस प्रोग्राम में प्रदूषण नियंत्रण उपायों के अलावा जन जागृति की भी व्यवस्था है। लोकहित की कोई भी योजना बिना लोगों की बृहद भागीदारी के संभव नहीं है। औद्योगिक, नगरीय और कृषि विकास सब मनमाने तौर पर संचालित किया जा रहा है। आमजन को शिक्षित-प्रशिक्षित करना, उन्हें कानून की इज्जत करना सिखाना भी परियोजना का हिस्सा होना चाहिए। आमजन के बीच जागरूकता की कमी के कारण ही उत्तराखंड हाइकोर्ट को मल-त्याग तक के लिए आदेश जारी करना पड़ा। लोगों को स्वयं अपने रहन-सहन में बदलाव लाना होगा, नहीं तो किसी प्रकार के प्रदूषण में कमी लाना असंभव नहीं, तो कठिन अवश्य है। साथ ही समस्त परियोजनाओं के लिए एक एकीकृत केंद्रीय क्रियान्वयन और नियंत्रण की आवश्यकता है। अन्यथा परियोजना पर परियोजना तैयार होती रहेंगी। आवंटित धन बेतहाशा खर्च होता रहेगा, कभी सफलता हासिल नहीं होगी और भ्रष्टाचार पनपता रहेगा।

Times Of India ND 29.12.2016 P-01

RBI gets its youngest dy guv post-reforms

TIMES NEWS NETWORK

Mumbai: A 42-year-old IITian, he is passionate about Kishore Kumar songs, has an album to his credit, and has now set a new record at the Reserve Bank of India.

Viral Acharya, named by RBI as its new deputy governor on Wednesday, comes with an unusual bag of talents and a formidable academic profile. The youngest deputy governor to be appointed after liberalisation, Acharya is the C V Starr professor of economics at New York University's Stern School of Business and earlier taught at London Business School.

Acharya fills in the vacancy created by the elevation of Urjit Patel as RBI governor.

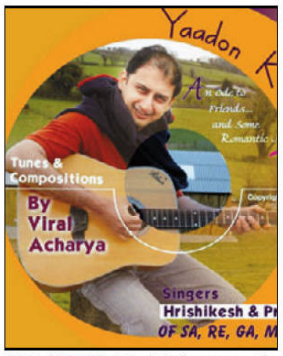

OLD NOTES: Viral Acharya on the cover of his music album

▶Worked with Rajan, P 18

Acharya closely associated with Rajan

▶Continued from P1

Of the four RBI deputy governors, two are internal appointees, NS Vishwanathan and R Gandhi. The one in charge of banking operations, SS Mundra, is a former bank chief. The fourth, who gets the portfolio of monetary policy and research, is always an economist.

Viral Acharya, who refers to fellow IITian Raghuram Rajan as "a great source of inspiration", has co-authored papers along with the erstwhile RBI chief. As a solo artist, Acharya has scored compositions and lyrics for a Hindi music album called 'Yaadon Ke Silsile – An ode to friends and some romantic moods.'

Known for his work in financial stability — an area of regulation which came into focus during the global financial crisis — the new RBI deputy governor is remembered for his views on public sector banks, which were published in a 2015 report that he jointly authored. Describing their condition as precarious, his report recommended recapitalisation, improved governance and privatization of some of the banks in the long run. The list of papers published by him runs into 20 pages.

An Indian-born, post-liberalization professional, Acharya went to college in the year in which Manmohan Singh delivered his epochal budget speech of 1991. He stood fifth in the joint entrance exam of the Indian Institute of Technology, Mumbai and went on to graduate in computer science. After graduation he moved to the US where he pursued a Ph.D in computer science for a year before deciding to shift gears to finance. He obtained his doctorate in finance.

In a post online, Acharya describes music as his passion. "I have a slight preference for Indian and Western classical music and a strong preference for light Indian film music, especially the songs composed by S D Burman and R D Burman and rendered by Kishore Kumar."

Acharya has had a close association with former governor Raghuram Rajan with whom he has authored half a dozen papers including one on "Sovereign Debt, Government Myopia and the Financial Sector" in 2013. The former governor is also one of his references in his CV. Like Rajan, Acharya also comes from an academic background and has also co-authored at least three papers with the former RBI governor.

Just like Rajan, Acharya has also been a strong votary of the independence of central banks and favoured them being "democratically accountable, yet be operationally independent from political influence".